(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1993-94 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक संतोषजनक नहीं था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ङ) अक्तूबर, 1993 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किये गये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नवीनतम त्वरित अनुमानों के अनुसार 1992-93 की 1.8 प्रतिशत विकास दर की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 1993 की समग्र औद्योगिक उत्पादन विकास दर 1.6 प्रतिशत थी। सरकार समय समय पर औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्तियों की समीक्षा करती है और औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

Provision of funds for issue of identity cards to voters

*49. SHRI N.E. BALARAM:
SHRI S.S. SURJEWALA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Election Commission has asked the State Governments to issue identity cards for voters within a specific period;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that many of the State Governments have demanded that the Centre should bear the expenditure for the same; and

(d) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. According to the time-schedule given by the Election Commission, award of contract to the agencies, completion of photography and lamination, completion of distribution of cards to electors (inlcuding consignment of duplicates) is to be completed by 28.2.94, 31.8.94 and 30.11.94 respectively.

(c) and (d) Most of the State Governments have expressed their inability to raise necessary resources for implementation of the scheme of photo indentity cards and have asked the Central Government to bear the entire cost of the scheme. The Central Government is examining various aspects of the issue including one relating to funding of the scheme.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजी निवेश में वृद्धि

*50. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1994 में मार्च, 1993 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 246 उपक्रमों में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1995 में तथा मार्च, 1993 में इन उपक्रमों में कुल कितना-कितना पूंजी निवेश था;

(ग) क्या यह भी सच है कि मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इन उपक्रमों में होने वाली वित्तीय हानि की प्रतिशतता मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तुलना में इनमें कुल पूंजी के संदर्भ में कम थी;

(घ) यदि नहीं, तो मार्च, 1992 तथा मार्च, 1993 में हानि की अलग-अलग प्रतिशतता कितनी थी;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन उपक्रमों में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ा दिये जाने की बावजूद वित्तीय हानि में कोई कमी नहीं आयी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस संबंध में सरकार ने कार्यान्वयन हेतु क्या कार्य योजना तैयार की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जी हां, महोदय। 31 मार्च, 1990 तथा 31 मार्च, 1993 तक सामान्य शेयर एवं ऋण के रूप में कुल पूंजी निवेश क्रमश: 93,329 करोड़ रुपये तथा 1,46,971 करोड़ रुपये का था।

(ग) और (घ) मार्च, 1990 एवं मार्च, 1993 की अवधि के बीच केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में लगी हुई पूंजी के प्रतिशत के रूप में उनकी सकल लाभकारिता में कोई कमी नहीं आई है।

(ङ) प्रसंगाधीन अवधि में घाटा उठाने वाले 104 उद्यमों में से 77 उद्यमों में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है। इनमे से 28 उद्यमों ने वर्ष 1989-90 की तुलना में अपने घाटे में कमी की है। शेष 49 उद्यमों में उसी अवधि के दौरान घाटे में वृद्धि हुई है।

(च) सरकारी उद्यमों में कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु किए गए कुछेक उपायों का उल्लेख 23 फरवरी, 1994 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या 1 एवं 150 पर किया गया है। नवीकरण / पुनर्स्थापना योजनाओं के निर्माण हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल 45 रुग्ण उद्यमों को पंजीकृत कर चुका है।

रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन सौदा

*51. **श्री राम गोपाल यादव:**
श्री सुरेश पचौरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन सौदे के सिलसिले में एक और समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है तथा इस सौदे से भारत को क्या प्राप्ति होने की संभावना है और कब तक?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु उर्जा तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) भू-राजनैतिक विकासों के घटनाक्रम के परिणामस्वरूप रूस की ग्लेवकास्मॉस ने 1991 के मूल करार की अनिवार्य बाध्यता धारा का अक्तूबर 1993 में प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप उसी समय से टेक्नालॉजी का स्थानान्तरण और प्रशिक्षण कार्य रुक गया। तदनन्तर इसरो और ग्लेवकास्मॉस के बीच दिसम्बर 1993 के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में करार पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की हल्दिया इकाई में लाभदायक बेरोज़गारी

*52. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री जी. वाई. कृष्णन:

क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गेनफुली अनएम्पलॉयड फॉर 15 इयर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के हल्दिया संयंत्र में लगभग 1600 कर्मचारी बिना कोई कार्य किए हुए अपने मासिक वेतन के रूप में लगभग 18 करोड़ रुपए प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को अब तक लगभग 240 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) की हल्दिया परियोजना को आरम्भण अवधि के दौरान बारंबार उपस्कर खराबियों के कारण चालू नहीं किया जा सका। आरम्भण क्रियाकलापों को अक्तूबर, 1986 में रोक दिया गया था क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि परियोजना का सुचारू रूप से आरम्भण तथा व्यवहार्य प्रचालन किया जा सकेगा। तत्पश्चात हल्दिया परियोजना के पुनर्वास/पुनरुद्धार के प्रयास के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया किन्तु एक भी विकल्प व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि उत्पादन लागत बहुत अधिक आ रही थी। इसी बीच एच एफ सी को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रूग्ण कम्पनी घोषित किया गया है। एच एफ सी के पुनर्वास, जिसमें इसकी हल्दिया परियोजना भी शामिल है, के संबंध में कोई कार्यवाही बी आई एफ आर, जो एक न्यायिक कल्प है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा। इस समय, लगभग 1555 कर्मचारी इस परियोजना से सम्बद्ध हैं। कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि और ग्रेच्यूटी पर प्रतिमाह 72.63 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है।